भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2948
05.08.2026 को उत्तर देने के लिए

ग्रामीण परिवारों की औसत वार्षिक और मासिक आय

2948. डॉ. मोहम्मद जावेदः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में विशेषकर विहार में ग्रामीण परिवारों की औसत वार्षिक और मासिक आय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार में औसत ग्रामीण आय कम होने के कारणों की जांच करने के निए कोई सर्वेक्षण, अध्ययन या मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान रोजगार सृजन, कौशल विकास कृषि विविधीकरण, ग्रामीण उद्यमिता, स्वरोजगार, बाजार पहुंच और आजीविका संवर्धन के लिए की गई पहलों सहित बिहार में ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए गए और प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है और इन पहलों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग): राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा ग्रामीण परिवारों की औसत आय का वार्षिक अनुमान नहीं लगाया जाता है।

तथापि, नाबार्ड द्वारा वर्ष 2016-17 के संदर्भ में आयोजित पहले अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफआईएस) और वर्ष 2021-22 के संदर्भ में आयोजित दूसरे एनएएफआईएस के आधार पर, बिहार सहित 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार, देश के ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय पांच वर्षों की अवधि में 57.6% बढ़कर वर्ष 2016-17 के ₹8,059 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹12,698 हो गई।

एनएएफआईएस वर्ष 2021-22 के परिणाम वर्ष 2016-17 में हुए पिछले सर्वेक्षण के बाद से ग्रामीण वित्तीय समावेशन में हुई उल्लेखनीय प्रगति को उजागर करते हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री

ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), मुद्रा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पीएम विश्वकर्मा आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किफायती ऋण तक पहुंच ने ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

*****